

## चुनावी खर्च सीमा में बढ़ोतरी

### प्रिलमिस के लिये:

भारतीय चुनाव आयोग (ECI), लागत मुद्रास्फीति सूचकांक

### मेन्स के लिये:

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951, नज़ी सदस्य वधियक

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय चुनाव आयोग](#) (ECI) द्वारा लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिये खर्च की सीमा 54 लाख-70 लाख रुपए (राज्यों के आधार पर) से बढ़ाकर 70 लाख-95 लाख रुपए कर दी गई थी।

- इसके अलावा विधानसभा क्षेत्रों के लिये खर्च की सीमा 20 लाख-28 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख- 40 लाख रुपए (राज्यों के आधार पर) कर दी गई थी।
- वर्ष 2020 में [चुनाव खर्च की सीमा का अध्ययन](#) करने हेतु चुनाव आयोग ने एक समिति का गठन किया था।

## प्रमुख बढि

- **परचिय**
  - 40 लाख रुपए की बढी हुई राश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में तथा 28 लाख रुपए की गोवा और मणपुर में लागू होगी।
  - कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में 10% की वृद्धि के अलावा उम्मीदवारों के लिये खर्च सीमा में अंतिम बड़ा संशोधन वर्ष 2014 में किया गया था।
  - समिति ने पाया कि वर्ष 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में काफी वृद्धि हुई है।

## लागत मुद्रास्फीति सूचकांक:

- इसका उपयोग मुद्रास्फीति के कारण वर्ष-दर-वर्ष वस्तुओं और संपत्तियों की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिये किया जाता है।
- इसकी गणना कीमतों और मुद्रास्फीति दर के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु की जाती है। सरल शब्दों में समय के साथ मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि होगी।
- लागत मुद्रास्फीति सूचकांक= तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) में औसत वृद्धि का 75%।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कीमतों में वृद्धि की गणना करने के लिये पिछले वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की एक ही बास्केट की लागत के साथ वस्तुओं व सेवाओं (जो अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है) की वर्तमान कीमत की तुलना करता है।
- केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना करके CII को नरिदष्टि करती है।

### ■ चुनाव व्यय सीमा:

- यह वह राशि है जो एक उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च की जा सकती है जिसमें सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, वजिजापनों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और वजिजापनों पर खर्च शामिल होता है।
- जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act-RPA), 1951 की धारा 77 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक किये गए सभी व्यय का एक अलग और सही खाता रखना होता है।
- चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर सभी उम्मीदवारों को ECI के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना होता है।
- उम्मीदवार द्वारा सीमा से अधिक व्यय या खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर RPA, 1951 की धारा 10 के तहत ECI द्वारा उसे तीन साल के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

- ECI द्वारा नरिधारति व्यय सीमा चुनाव के दौरान कयि जाने वाले वैध खर्च के लयि नरिधारति है क्योकचि चुनाव में बहुत सारा पैसा गलत एवं अवांछति कार्यों पर खर्च कयि जाता है ।
- अक्सर यह तर्क दयि जाता है कचि चुनावी खर्च की यह सीमा अवास्तवकि है क्योकचि उम्मीदवार द्वारा कयि गया खर्च वास्तवकि व्यय से बहुत अधिक होता है ।
- उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान अधिकतम खर्च की सीमा के नरिधारण के संदर्भ में दसिंबर 2019 में एक नजिी सदस्य द्वारा संसद में बलि पेश कयि गया-
- यह कदम इस आधार पर उठायि गया कचि प्रत्याशयिों के चुनाव खर्च के संबंध में कसिी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा खर्च की कोई उच्चतम सीमा नरिधारति नहीं है, जसि कारण अक्सर राजनीतिक पार्टयिों द्वारा उम्मीदवारों का शोषण कयि जाता है ।
- हालाँकचि सभिी पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव पूरा होने के 90 दनिों के भीतर चुनाव आयोग को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा प्रस्तुत करना होता है ।

## राज्य अनुदान पर सफिारशियें:

- **इंदरजीत गुपुता समति (1998)** द्वारा यह सुझाव दयि गया कचि राज्य द्वारा वतितपोषण आर्थकि रूप से कमजोर राजनीतिक दलों के लयि एक समान आधार को सुनश्चिति करेगा एवं ऐसा कदम सार्वजनकि हति में होगा ।
- यह भी सफिारशि की गई कचि राज्य द्वारा यह धन केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को दयि जाना चाहयि तथा यह आर्थकि सहायता उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली मुफ्त सुवधायिों के रूप में दी जानी चाहयि ।
- **वधिआयोग की रपिाट (1999) के अनुसार**, राजनीतिक दलों को चुनाव के लयि राज्य द्वारा वतितयि सहायता देना वांछनीय/उचति (Desirable) है, बशर्ते राजनीतिक दल अन्य स्रोतों से आर्थकि सहायता प्राप्त न करे ।
- **संवधान के कामकाज की समीक्षा के लयि गठति राष्ट्रीय आयोग (वर्ष 2000)** द्वारा इस वचिार का समर्थन नहीं कयि गया लेकनि इसके द्वारा उल्लेख कयि गया कचि राजनीतिक दलों के नयिमन के लयि एक उपयुक्त रूपरेखा को राज्य द्वारा वतितपोषण से पहले लागू करने की आवश्यकता है ।

## आगे की राह

- **राज्यों द्वारा चुनाव की फंडगि:** इस प्रणाली में राज्य द्वारा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च वहन कयि जाता है ।
  - यह प्रणाली वतितपोषण प्रक्रयिा में पारदर्शति ला सकती है क्योकचि यह चुनावों में इच्छुक सार्वजनकि वतितदाताओं के प्रभाव को सीमति कर सकती है तथा इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मलियी ।

## स्रोत- द हदि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/increased-election-expenditure-limit>